

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)(231)नियम/डीएलबी/19/36852-37044  
आयुक्त/अधिकाधी अधिकाधी,  
नगर निगम/परिषद/पालिका,  
समस्त, राजस्थान।

दिनांक 25/11/2019

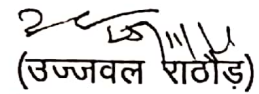
विषय:—शहरो में विभिन्न मार्गो पर ऑप्टिक फाइवर केबल डालने एवं जी.बी.एम. निर्माण की अनुमति देते समय क्षति ग्रस्त सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से प्राप्त/वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में।

प्रसंग:—विभागीय पत्र क्रमांक प.8(ग)(203)नियम/डीएलबी/19/32208-32404  
दिनांक 30.08.19 के क्रम में।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा शहरो में विभिन्न मार्गो पर ऑप्टिक फाइवर केबल डालने एवं जी.बी.एम. निर्माण की अनुमति देते समय क्षति ग्रस्त सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से प्राप्त/वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट-II दिनांक 31.08.12 के बिन्दु संख्या 5 के संबंध में प्रकरण विशेष हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

प्रासंगिक पत्र के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट-III दिनांक 06.02.17 द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट-II दिनांक 31.08.12 को अतिक्रमित किया जा चुका है एवं नगरीय विकास विभाग का आदेश दिनांक 06.02.17 ही प्रभावी है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.02.17 के प्रावधानो के अनुसार ही सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से पूर्ण राशि प्राप्त/वसूल की जावे।

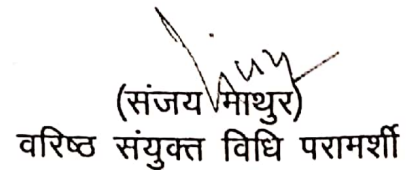
  
(उज्जवल राठोड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
दिनांक 25/11/2019

क्रमांक: प.8(ग)(231)नियम/डीएलबी/19/37045-37047  
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त शासन सचिव, III नगरीय विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
3. सुरक्षित पत्रावली।

4. हाथानट, निदेशालय जयपुर को विभागीय  
वेबसाइट पर अपलोड कवाने काबत।

  
(संजय मिश्र)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी